(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय/सलाह ली है अथवा लिये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) प्रसार भारती विधेयक, 1989 लोक सभा में दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक पर इसी महीने संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार किए जाने और इसे पारित किए जाने की संभावना है।

(ख) सरकार के प्रसार भारती विधेयक के बारे में प्रसारण क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित राज्य सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों की राय मांगी है।

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने के संबंध में ज्ञापन

853. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दलों ने दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में सरकार को ज्ञापन दिये हैं? और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) - (दिल्ली राज्य समिति) का विचार है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाये, लेकिन केन्द्र सरकार की आवश्यकताओं जैसे नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्राधिकार पर विशेष ध्यान दिया जाये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (दिल्ली राज्य परिषद) का विचार है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये, और अधिक से अधिक, नई दिल्ली क्षेत्र के एक भाग को संघ शासित क्षेत्र बनाए रखा जाये। दिल्ली प्रदेश जनता दल का विचार है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाय और राज्य विधान सभा में 84 सदस्य हों। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई का विचार है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाये और नागरिक प्रशासन के भावी ढांचे का निर्णय, जब राज्य विधान सभा अस्तित्व में आए, तो उस पर छोड़ दिया जाये। मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Multi-level response to challenges of secessionist, communal and extremist organisations

854. SHRI BEKAL UTSAHI:
DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to evolve a Multi-level response to meet the challenges thrown up by sessionist, communal and extremist organisations; and

(b) if so, the deatils thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) Some anti-national forces have sinister designs to destabilise the unity of the country. Their ugly plans have to be effectively countered by a determined nation. The National Integration Council in its meeting on 11th April, 1990 has appealed for mobilisation of all nationalist democratic and secular forces to meet the challenge of violence, secessionism, communalism and fundamentalism. Government is determined to ensure that a durable climate of communal harmony, stability and progress prevails throughout the country. All necessary help and assistance is being provided by the Central Government to the States concerned to maintain peace and communal harmony.